Statement

Ministry of Urban Development

Centrally sponsored accelerated Urban Water Supply programme (Auwsp) list of schemes town-wise approved for allocation of central assistance during annual plan **1993-94**

STATE: GUJARAT (RS. LAKHS)

S.No.	Name of Town	District	Population (1991 Census)	Service level (LPCD) (Present /proposed)	Category of the scheme New/ Augmentation Rehabilitation	Estimated cost (As on 1991)	Per Capital cost (Rs)	Central share 50% of Col.7	Central release 25% of the approved Central share
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dharampur	Valsad	16584	15/70	Aug.	47.42	286.00	23.71	5.93
2.	Bantva	Junagadh	15394	15/70	Aug.	68.89	448.00	34.45	8.61
3.	Dhrol	Jamnagar	17060	16/70	Aug.	130.00	762.00	65.00	16.25
4.	Suraj-kabadi	Jamnagar	14325	14/70	Aug.	80.00	556.00	40.00	10.00
5.	Okhaport	Jamnagar	13342	14/70	Aug	55.00	412.00	27.50	6.88
6.	Jodia	Jamnagar	12083	16/70	Aug.	92.13	762.00	46.07	11.52
7.	Barwala	Ahmedabad	13485	15/70	Aut.	38.89	288.00	19.45	4.86
8.	Mendarda	Junagadh	13142	19/70	Aug.	56.29	428.00	28.15	7.04
		TOTAL:				568.62		284.31	71.08

Habitat projects for Madhya Pradesh

1693. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh has sent some habitat projects for various cities of the State;

(b) if so, the details of these projects; and

(c) by when these projects are likely to be cleared by the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) The Government of Madhya Pradesh had submitted a project profile seeking, inter-alia, a loan assistance of Rs. 109.50 crores from Asian Development Bank for construction of houses for economically weaker sections in the cities of Raipur, Jabalpur, Bhopal, Gwalior and Indore. The proposal had been examined and certain deficiencies therein with regard to viability and feasibility of the project had been pointed out to

the State Government in March, 1994 with the advice to recast the proposals, keeping in view the observations made. The recast proposal has not been received from the State Govt. till date.

आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) की सहायता के आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन

1694. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र के राजकोट, जाम नगर, भावनगर, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) की सहायता से कार्यान्वित की गई आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के मामले में लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान जिलेवार कितने आवासों का निर्माण किया जायेगा;

(घ) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमश: जिलेवार कितने परिवारों को आवासों का आबंटन किया गया है ;

(ङ) कितने मामलों में आवासों को रहने/निवास करने योग्य नहीं पाये जाने के कारण आबंटित नहीं किया गया है;

(च) ऐसे आवासों की संख्या कितनी है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(छ) इन आवासों को रहने के योग्य न पाये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा क्या सरकार ने उक्त मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों को कोई अनुकरणीय दंड दिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1–4–91 से 30–6–94 तक की अवधि के दौरान हुडको ने राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में 8683 मकानों के निर्माण के लिये 28.64 करोड़ रु० की ऋण-सहायता स्वीकृत की है। स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

जिला का नाम	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रु०)	रिहायशी एकक
राजकोट	10	14.80	4232
जामनगर	6	4.07	1972
भावनगर	8	5.77	1509
जूनागढ़	4	3.29	800
कच्छ	1	0.71	170
	29	28.64	8683